वाईएस जगन मोहन रेड्डी

बनाम

सीबीआई

(2013 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3404 से उत्पन्न)

9 मई, 2013

[पी. सदाशिवम,एम. वाई. इकबाल जे.जे.]

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973:

एस.एस.439 और 173(8)- जमानत- आर्थिक अपराध- कारक जिन्हें जमानत देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए- समझाया गया- धारा 420, 409 और 477-ए भारतीय दण्ड संहिता आैर धारा 13(2) के साथ पठित धारा के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(सी)- अवैध रूप से भारी मात्रा में अर्जित धन इकट्ठा करने, शिथिल मानदंडों पर भूमि आवंटन, सार्वजनिक पद का दुरुपयोग, फर्जी कंपनियों में निवेश के माध्यम से रिश्वत के धन को सफेद करने आदि से संबंधित आरोप- आगे की जांच प्रगति पर है- अभिनिर्धारित: गहरी साजिशों वाले और सार्वजनिक धन की भारी हानि वाले आर्थिक अपराधों को गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसे गंभीर अपराध माना जाना चाहिए जो पूरे देश

की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और जिससे देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। , और एक वर्ग से अलग होने के नाते, उन्हें जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ जांच करने की आवश्यकता है - आगे बढ़ने पर सीबीआई द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट और पुलिस उप महानिरीक्षक और मुख्य जांच अधिकारी द्वारा दिए गए जवाबी हलफनामे के अनुसार, इस स्तर पर अपीलकर्ता की रिहाई से जांच में बाधा आएगी क्योंकि यह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और भौतिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है- हालांकि, सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वह मामले को पूरा करे। तेजी से जांच करें और आरोप पत्र दाखिल करें- इसके बाद, अपीलकर्ता जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत करने के लिए स्वतंत्र है ।

उच्च न्यायालय के आदेश पर, सीबीआई ने दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भारी अवैध संपत्ति अर्जित करने, ऐसे पैसे से मीडिया व्यवसाय चलाने, बेनामी शेयर धारकों के साथ फर्जी कंपनियां चलाने से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया। और ऐसी कंपनियों में निवेश, भूमि आवंटन, सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग, सिंचाई परियोजनाओं के अनुबंध, रियल एस्टेट उद्यमों, खानों आदि के लिए विशेष छूट/अनुमतियां आदि के माध्यम से रिश्वत के पैसे का शोधन किया गया। अपीलकर्ता, एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, पर आरोप लगाया गया था जैसा कि आरोपी नं. मामले में 1 अन्य के साथ। मामले

में चार आरोप पत्र क्रमशः 31.3.2012, 23.4.2012, 7.5.2012 और 13.8.2012 को दायर किए गए थे। अपीलकर्ता को 29.5.2012 को गिरफ्तार किया गया था। समय-समय पर दायर की गई उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। अपीलकर्ता ने 16.11.2012 को फिर से डिफ़ॉल्ट/नियमित जमानत के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष असफल आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने भी उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारितः 1.1. आर्थिक अपराध एक वर्ग का गठन करते हैं आैर जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ जांच करने की आवश्यकता है । ऐसे अपराधों की जड़ें बहुत गहरी हैं षडयंत्र और इसमें सार्वजनिक धन की भारी हानि शामिल है, इसे गंभीरता से देखने और गंभीर मानने की जरूरत है ऐसे अपराध जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और इस प्रकार देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। [पैरा 15) [561-डी-ई]

1.2. मौजूदा मामले में स्टेटस रिपोर्ट में सी.बी.आई ने आश्वासन दिया है कि जांच की जा रही है इस न्यायालय के निर्देशानुसार शीघ्रता से। यह कहा गया है दिनांकित पूर्व आदेश में उल्लिखित 7 मुद्दों में से इस कोर्ट की जी 5.10.2012 को सीबीआई ने पूरी कर ली है एक मामले के संबंध में जांच और अन्य 6 मुद्दों के संबंध में भी जांच प्रगति पर है और उनमें से

तीन के संबंध में जांच अंतिम चरण में है, जिसमें जल्द ही आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने की संभावना है। [पैरा एच 1 ओजे (556-एफ-एच)

1.3. जमानत देते समय कोर्ट को ध्यान रखना होगा आरोपों की प्रकृति, साक्ष्य की प्रकृति उसका समर्थन, सजा की गंभीरता जो दोषसिद्धि में शामिल होगा, अभियुक्त का चरित्र, परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं, बी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना मुकदमे में आरोपी की उचित आशंका गवाहों के साथ छेड़छाड़, जनता/राज्य के व्यापक हित

1.4. सी में सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत सभी विवरणों पर गौर करने पर स्थिति रिपोर्ट का प्रपत्र और प्रति शपथ पत्र दिनांकित 06.05.2013 को उप महानिरीक्षक द्वारा शपथ दिलाई गई पुलिस और मुख्य जांच अधिकारी, मामले की विशालता और आरोप पत्र दाखिल करने में जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने के सीबीआई के अनुरोध पर, यह अदालत का है। राय है कि इस स्तर पर अपीलकर्ता की रिहाई से जांच में बाधा आ सकती है। इस दावे पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता बड़े मौद्रिक लेनदेन में अंतिम लाभार्थी और मुख्य साजिशकर्ता है, सीबीआई द्वारा उठाई गई आशंका को हल्के से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि, सीबीआई को जांच तेजी से पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत

के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत करने के लिए स्वतंत्र है। [पैरा 14 और 17] [561-बी, जी-एच; 562-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या. 730/ 2013

उच्च न्यायालय ए. पी., हैदराबाद 2012 के सी. आर. एल. पी. सं. 8750 के निर्णय और आदेश दिनांक 24.01.2013 से।

हरीश एन. साल्वे, मुकुल रोहतगी, सुशील कुमार, के. वी. विश्वनाथन, गोपाल शंकरनारायण, नीरंजन रेड्डी, श्रीराम, सुभाष रेड्डी, सेंथिल जगदीशन, अपीलार्थी के लिए अशोक भान, मुकुल गुप्ता, डी. एल. चिदानंद, अंजलि चौहान, बी. वी. बलरामदास प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया

पी. सतशिवम, जे.(1) याचिका स्वीकृत ।

(2) यह अपीलआंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा आरसी 19(ए)/2011-सीबीआई-हैदराबाद में 2012 की आपराधिक याचिका संख्या 8750 में दिनांक 24.01.2013 को पारित किया गया अंतिम निर्णय और आदेश, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत के लिए याचिका को खारिज कर दिया,के विरुद्ध निर्देशित है।

(3) विचार के लिए रखा गया एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला बनाया है।

संक्षिप्त तथ्य:

(4) (ए) 2011 की रिट याचिका संख्या 794, 6604 और 6979 दिनांक 10.08.2011 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में "सीबीआई"), हैदराबाद ने एक मामला दर्ज किया। मामला आरसी नंबर 19(ए)/2011-सीबीआई-हैदराबाद दिनांक 17.08.2011 को धारा 120बी के तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 409 और 477-ए (संक्षेप में ' आईपीसी ') और धारा 13 के साथ पढ़ा जाता है। 2) वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1), संसद सदस्य और 73 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में " पीसी अधिनियम ") की धारा 13(1)(सी) और (डी) के साथ पढ़ें ।

(बी) अपीलकर्ता-वाईएस जगन मोहन रेड्डी को एसएल में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। दिनांक 17.08.2011 की एफआईआर में नंबर 1 (आरोप पत्र तय होने के बाद, उसे ए-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इसके बाद, उसे ए-1 के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

(सी) जांच के दौरान, यह पता चला कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1), आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाए, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी सार्वजनिक क्षति हुई। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने बेटे वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) के लाभ के लिए अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया। मई, 2004 से, ए-

1 ने मेसर्स जगती पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियां शुरू कीं। लिमिटेड, जिसे मूल रूप से 14.11.2006 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और बाद में 12.01.2009 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। प्रासंगिक समय पर, वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) को उक्त कंपनी के बैंक खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्हें 21.06.2007 से निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि ए-1 ने मेसर्स जगती पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। लिमिटेड का उद्देश्य अवैध कमाई से मीडिया व्यवसाय चलाना है। अधिकांश शेयरधारकों पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) के बेनामी होने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, इन निवेशों के बदले में, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए भूमि आवंटन, सिंचाई परियोजनाओं के अनुबंध, विशेष छूट/ में राज्य सरकार के निर्णयों से कंपनियों/व्यक्तियों सहित विभिन्न निवेशकों को लाभ प्राप्त हुआ। रियल एस्टेट उद्यमों, खदानों आदि के लिए अनुमति। आगे यह पता चला है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) ने रिश्वत के पैसे को विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों के माध्यम से भेजकर और उच्च प्रीमियम पर अपनी कंपनियों में उनके द्वारा निवेश करवाकर शोधन किया।

(डी) 31.03.2012, 23.04.2012 और 07.05.2012 को, सीबीआई ने सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद के समक्ष क्रमशः पहला,

दूसरा और तीसरा आरोप पत्र दायर किया और अपीलकर्ता को कुल मिलाकर ए-1 के रूप में सूचीबद्ध किया गया। आरोप पत्र. सीबीआई मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 31.03.2012 के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जिसे 2012 की सीसी संख्या 8 के रूप में क्रमांकित किया गया था। अपीलकर्ता को मामले में उसकी संलिप्तता और मिलीभगत के लिए 27.05.2012 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान मे वह्जेल में है। न्यायिक हिरासत. 29.05.2012 और 30.05.2012 को, सीबीआई मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश ने दूसरे और तीसरे आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जिन्हें क्रमशः 2012 के सीसी नंबर 9 और 10 के रूप में क्रमांकित किया गया था।

(ई) 29.05.2012 को, अपीलकर्ता ने सीआरएल दायर किया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 437 के तहत नियमित जमानत देने के लिए हैदराबाद में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत के समक्ष 2012 के सीसी नंबर 8 में एमपी नंबर 1055/2012। विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 01.06.2012 के आदेश से उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

(एफ) सीबीआई ने 5 दिनों की अवधि के लिए ए-1 की रिमांड के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 की आपराधिक याचिका संख्या 4743 और 4744 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.06.2012 के आदेश द्वारा, याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और ए-1 को 03.06.2012 से

07.06.2012 तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। आगामी आदेश दिनांक 08.06.2012 द्वारा सी.आर.एल. 2012 की आपराधिक याचिका संख्या 4743 में 2012 की एमपी संख्या 4785, हिरासत को 2 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

(जी) व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने 2012 की आपराधिक याचिका संख्या 5211 में उसे जमानत पर बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने, अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और अपीलकर्ता के व्यक्तिगत और वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए (ए-1) और यह पाते हुए कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस चरण में जमानत पर रिहा होने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, दिनांक 04.07.2012 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

(एच) दिनांक 02.06.2012 और 04.07.2012 के आदेशों से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2012 की दो विशेष अनुमति याचिकाएँ संख्या 5901 और 5902 प्रस्तुत कीं। इस न्यायालय ने दिनांक 09.08.2012 के आदेश द्वारा एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 5902/2012 में नोटिस जारी किया और एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 5901/2012 को खारिज कर दिया।

(आई) 13.08.2012 को, सीबीआई ने हैदराबाद के सीबीआई मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश की अदालत में चौथा आरोप पत्र दायर किया, जिसे 2012 के सीसी नंबर 14 के रूप में क्रमांकित किया गया था।

(जे) इस न्यायालय को यह पता चलने पर कि 7 मामलों के संबंध में जांच जारी है, विशेष अनुमति याचिका 2012 की एसएलपी (सीआरएल) 5902 को दिनांक 05.10.2012 के आदेश से खारिज कर दिया और सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मामले को पूरा करे। शेष 7 मुद्दों पर यथाशीघ्र जांच कर समेकित आरोप पत्र दाखिल करने को कहा। इस अदालत ने अपीलकर्ता को सीबीआई द्वारा जांच पूरी होने पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत करने का भी निर्देश दिया।

(के) 16.11.2012 को, अपीलकर्ता ने सीआरएल दायर किया। एमपी नंबर 1938/2012, हैदराबाद के सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष डिफॉल्ट/वैधानिक जमानत की मांग। उसी दिन, अपीलकर्ता ने सी.आर.एल. दायर किया। एमपी नंबर 1939/2012 में सीसी नंबर 8/2012 में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद के समक्ष नियमित जमानत की मांग की। दिनांक 28.11.2012 और 04.12.2012 के आदेश से, विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा सीआरएल में दायर जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 2012 का एमपी नंबर 1938 और सीआरएल। क्रमशः 2012 का एमपी क्रमांक 1939।

(एल) अपीलकर्ता ने जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 की आपराधिक याचिका संख्या 8576 दायर की, जो 24.12.2012 को खारिज कर दीगई। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक याचिका संख्या 8750/2012 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.01.2013 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

(एम) उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

(5) अपीलकर्ता-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश एन. साल्वे, श्री मुकुल रोहतगी और श्री केवी विश्वनाथन और प्रतिवादी-सीबीआई के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक भान और श्री मुकुल गुप्ता को सुना।

(6) सीबीआई ने 06.05.2013 को एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी, अर्थात् पुलिस उप महानिरीक्षक और आरसी संख्या 19(ए)/2011-सीबीआई-एचवाईडी में मुख्य जांच अधिकारी ने शपथ ली है और विभिन्न जानकारी प्रस्तुत की है। जैसे अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप, शामिल कंपनियां/व्यक्ति, अब तक की गई जांच और कुछ कंपनियों/व्यक्तियों के संबंध में जांच की प्रगति। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने इस न्यायालय के दिनांक 05.10.2012 के आदेश में उल्लिखित 7 मुद्दों के संबंध में एफआईआर संख्या 19(ए)/2011-सीबीआई-एचवाईडी के संबंध में स्थिति रिपोर्ट भी प्रसारित की। अपीलकर्ता की ओर

से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस तथ्य सहित विभिन्न सामग्रियों/विवरणों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अपीलकर्ता लगभग 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में है और उन लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाने वाले कई व्यक्ति हिरासत में नहीं हैं और न ही उनकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई द्वारा कदम उठाए गए हैं, प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता को उचित शर्तें लगाने के बाद जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

(7) प्रतिद्वंद्वी तर्कों, विशेष रूप से, सीबीआई के रुख की सराहना करने के लिए, इस न्यायालय द्वारा 05.10.2012 को पारित पहले के आदेश को संदर्भित करना उपयोगी होगा जो इस प्रकार है:

"एसएलपी (सीआरएल.)नं. 5902 ऑफ़ 2012 में

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम को विस्तार से सुना गया।

सीबीआई की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री मोहन परासरन ने हमारे समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे यह प्रतीत होता है कि सात मामलों के संबंध में जांच अभी भी जारी है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 9 में इसे इस प्रकार बताया गया है:

> "...जिन मामलों की जांच लंबित है, उनमें सैकड़ों करोड़ रुपये से जुड़े विभिन्न गंभीर आर्थिक अपराधों की जांच भी शामिल है। जिन प्रमुख मामलों की अब जांच चल रही है, वे

साजिशों से संबंधित हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं, जो स्वयं एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और इसलिए, अलग-अलग साजिशें हैं।

(i) संदुर पावर कंपनी लिमिटेड

(ii) भारती सीमेंट्स/रघुराम सीमेंट्स को खनन पट्टा प्रदान करना, जो कोई और नहीं बल्कि A1, श्री जेएमआर की अपनी कंपनियां हैं।

(iii) पेन्ना सीमेंट्स और समूह कंपनियां

(iv) डालमिया सीमेंट्स

(v) इंडिया सीमेंट्स

(vi) कोलकाता और मुंबई स्थित कागजी कंपनियों के माध्यम से निवेश, जिन्हें आम तौर पर सूट केस कंपनियों के नाम से जाना जाता है।

(vii) इंदु प्रोजेक्ट्स, लेपाक्षी नॉलेज हब

अनुमान के अनुसार उपरोक्त मामलों में शामिल राशि और जो जांच का विषय है, 3000 करोड़ रुपये से अधिक है। (मूल में जोर)

श्री परासरन ने कहा कि सीबीआई बिना समय बर्बाद किए जांच कर रही है और उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया

कि जांच जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और जांच पूरी होने पर सीबीआई एक अंतिम आरोप पत्र दाखिल करेगी। .

पक्षों के वकील को सुनने और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को देखने के बाद, हम इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

हालाँकि, ऊपर बताए गए मुद्दों पर सीबीआई द्वारा जांच पूरी होने और अंतिम आरोप-पत्र प्रस्तुत करने पर याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत करने के लिए खुला होगा।

यदि ऐसी कोई प्रार्थना की जाती है, तो न्यायालय विशेष अनुमति याचिका के खारिज होने से प्रभावित हुए बिना, अपने गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से जमानत की प्रार्थना पर विचार करेगा।

2012 की एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 5946

दो सप्ताह बाद लगाई जाएगी।

(8) सीबीआई के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक भान ने दिनांक 05.10.2012 के आदेश में अंतिम पैराग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, "हालांकि, यह याचिकाकर्ता के लिए खुला होगा कि वह मुकदमे से पहले

जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत कर सके।"ऊपर बताए गए मुद्दों पर सीबीआई द्वारा जांच पूरी करने और अंतिम आरोप-पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत ने कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ कंपनियों/के साथ लेनदेन के संबंध में जांच अभी भी जारी है। व्यक्तियों, जमानत के लिए वर्तमान आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।

(9) यह नोट करना प्रासंगिक है कि दिनांक 05.10.2012 के आदेश में, इस न्यायालय ने विद्वान एएसजी द्वारा दिए गए बयान पर ध्यान दिया, जो सीबीआई की ओर से पेश हुए थे, कि साजिशों से संबंधित जांच में स्पष्ट रूप से 7 संस्थाएं शामिल थीं जो स्वयं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अतिरिक्त समय की आवश्यकता है. सीबीआई के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, उन्हें दिनांक 05.12.2012 के आदेश में उल्लिखित 7 संस्थाओं के संबंध में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दायर करने के लिए 4-6 महीने के समय की आवश्यकता है। उपरोक्त दावे के समर्थन में, सीबीआई ने जवाबी हलफनामे के साथ-साथ स्थिति रिपोर्ट से जमानत आवेदन को खारिज करने के लिए अपने रुख को उचित ठहराते हुए विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख किया।

(10) स्थिति रिपोर्ट में, सीबीआई ने आश्वासन दिया है कि इस न्यायालय के निर्देशानुसार जांच तेजी से की जा रही है। यह कहा गया है कि 7 मुद्दों में से, सीबीआई ने मेसर्स डालमिया सीमेंट्स के संबंध में जांच पूरी कर ली है और परिणामस्वरूप 08.04.2013 को हैदराबाद के सीबीआई

मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई के अनुसार, वर्तमान में, अन्य 6 मुद्दों के संबंध में भी जांच प्रगति पर है और सीबीआई निम्नलिखित के संबंध में जांच के अंतिम चरण में है, अर्थात, मेसर्स इंडिया सीमेंट्स, पेन्ना सीमेंट्स और कोलकाता की कंपनियों के माध्यम से निवेश। . इस न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया गया है कि सीबीआई द्वारा शीघ्र ही उपरोक्त तीन मुद्दों पर आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की संभावना है।

(11) सीबीआई ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में शेष मुद्दों की जांच के संबंध में प्रगति के बारे में विस्तार से बताया है जो इस प्रकार हैं:-

मेसर्स डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड।

(ए) जांच से पता चला है कि मेसर्स डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड ने रुपये की राशि का निवेश किया है। मेसर्स रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड में 95 करोड़ रुपये का प्रतिनिधित्व वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किया। निवेश के बदले में, ए-1 ने अपने पिता स्वर्गीय डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी पर अपने प्रभाव के माध्यम से आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में मेसर्स डालमिया सीमेंट्स को 407 हेक्टेयर की सीमा तक खनन पट्टे के अनुदान और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। . सीबीआई ने इसमें शामिल राशि और अपीलकर्ता के पिता द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं पर प्रकाश डाला है। स्थिति रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि आयकर विभाग,

नई दिल्ली द्वारा मेसर्स डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड के कार्यालयों और उनके कर्मचारियों के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई थी।

(बी) यह भी उजागर किया गया है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1), वी. विजय साई रेड्डी (ए-2) और पुनीत डालमिया के बीच पूर्व-निर्धारित समझौते के अनुसार, मेसर्स डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड। मेसर्स रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी मेसर्स PARFICIM, फ्रांस को कुल रु. में बेची। जिसमें से 135 करोड़ रु. वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) को 16.05.2010 और 13.06.2011 के बीच हवाला चैनलों के माध्यम से नकद में 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, और उक्त भुगतान का विवरण आयकर विभाग, नई दिल्ली द्वारा जब्त की गई सामग्री में पाया गया था।

सी) सीबीआई ने आगे आरोप लगाया है कि मेसर्स डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड ने हवाला चैनलों के माध्यम से वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए -1) को कथित बिक्री आय नकद में लौटा दी है जो स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि रुपये का प्रारंभिक भुगतान। 95 करोड़ रुपये केवल आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुचित लाभ के लिए अवैध संतुष्टि थी और वास्तविक निवेश नहीं था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आईपीसी और पीसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ए-1 और 12 अन्य के खिलाफ 08.04.2013 को आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है ।

मेसर्स संदुर पावर कंपनी लिमिटेड

(ए) मेसर्स संदुर पावर कंपनी लिमिटेड से संबंधित जांच के संबंध में, सीबीआई द्वारा कहा गया है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) 16.06.2001 से 11.01.2010 तक इस कंपनी के निदेशक थे। मेसर्स संदुर पावर कंपनी लिमिटेड की स्थापना 23.10.1998 को एमबी घोरपड़े द्वारा की गई थी और उसके बाद, वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) जून 2001 के दौरान निदेशक मंडल, यानी हरीश सी. कामर्थी और के साथ कंपनी में शामिल हुए। जे.जे. रेड्डी. सीबीआई का आरोप है कि कंपनी पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) का करीबी कब्जा है। सीबीआई ने रुपये के विभिन्न शेयर लेनदेन पर भी प्रकाश डाला। मैसर्स संदुर पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा मॉरीशस स्थित दो कंपनियों, मैसर्स 2आई कैपिटल और मैसर्स प्लुरी इमर्जिंग कंपनी के साथ 124.60 करोड़ रुपये। सीबीआई द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि उपरोक्त राशि ए-1 की है जो कि थी मॉरीशस स्थित कंपनियों के माध्यम से भेजा गया। यह भी उजागर किया गया है कि निम्मगड्डा प्रसाद (ए-3) की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। इस साजिश के पीछे वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) के साथ विजय साई रेड्डी (ए-2) का दिमाग था, क्योंकि ए-2 ने चेन्नई में फर्जी कंपनियां खोली थीं ताकि एम/एम में राउंड ट्रिपिंग या पैसा भेजा जा सके। संदुर पावर कंपनी लिमिटेड ने चेन्नई के साथ-साथ कुछ विदेशी देशों में फर्जी तरीके से बनाई गई कंपनियों के माध्यम से भारत और विदेशों से धन प्राप्त किया।

(बी) सीबीआई द्वारा यह भी बताया गया है कि एक मयंक मेहता को भी नोटिस जारी किया गया है, जिस पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए -1) के पैसे के लेन-देन को संभालने वाला व्यक्ति होने का संदेह है और नोटिस जारी किया गया है। जांच और पूछताछ के लिए भारत में उसकी उपस्थिति के लिए। उक्त व्यक्ति वर्तमान में हांगकांग में स्थित है और तुच्छ कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर रहा है। ऐसा संदेह है कि वह वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) और विजय साई रेड्डी (ए-2) से प्रभावित हो रहे हैं, जो यह साबित करता है कि इस मामले में गवाहों को इन व्यक्तियों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है।

भारती सीमेंट्स/रघुराम सीमेंट्स को खनन पट्टे का अनुदान:

सीबीआई द्वारा यह बताया गया है कि भारती सीमेंट्स/रघुराम सीमेंट्स, जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, को चूना पत्थर के खनन पट्टे देने के संबंध मेंजांच प्रगति पर है। सीबीआई का दावा है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, उन्होंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जुबली हिल्स, हैदराबाद, कोरमंगला, बैंगलोर, प्रधान कार्यालय, गुड़गांव आदि सहित विभिन्न विभागों/बैंकों से हजारों पृष्ठों के लगभग 400 दस्तावेज़ एकत्र किए हैं। रुपये के ऋण के वितरण के लिए. बैंक दिशानिर्देशों और नियमों का उल्लंघन करते हुए 200 करोड़ रु. यह भी कहागया है कि जांच में रुपये के अवैध परितोषण के भुगतान का खुलासा हुआ। दो समुद्री बंदरगाहों और एक के विकास से संबंधित एक परियोजना

को आवंटित करने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से ए-3 द्वारा प्राप्त गलत लाभ के लिए निम्मगड्डा प्रसाद (ए- 3) द्वारा वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) को 30 करोड़ रुपये VANPIC परियोजना के रूप में औद्योगिक गलियारा और उक्त भुगतान आदि को छिपाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। मेसर्स इंदु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (मैसर्स लेपाक्षी नॉलेज हब प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंडस टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड) ने ने बताया कि उपरोक्त कंपनियों के समूह के संबंध में जांच जारी है। स्टेटस रिपोर्ट में, सीबीआई ने उन कंपनियों के साथ अपीलकर्ता की सांठगांठ के बारे में कई विवरण उजागर किए हैं। चूंकि उन कंपनियों के संबंध में जांच अभी भी प्रगति पर है, हम स्थिति रिपोर्ट में सीबीआई द्वारा प्रस्तुत उन सभी विवरणों को उजागर नहीं कर रहे हैं।

मेसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड

सीबीआई ने मेसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड से संबंधित जांच और पार्टियों के बीच आदान-प्रदान की गई विभिन्न रकमों पर प्रकाश डाला है। उपरोक्त के संबंध में, सीबीआई के अनुसार, उन्होंने वाईएस जगन मोहन रेड्डी (ए-1) की समूह कंपनियों में 140 करोड़ रुपये का अवैध निवेश किया था और कई लाभ प्राप्त किए थे। कागना और कृष्णा नदियों से पानी के उपयोग/अतिरिक्त मात्रा और भूमि के पट्टे के लिए अनुमति दी गई। यह भी बताया गया है कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, केवल कुछ और महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है। सीबीआई ने कोलकाता और

मुंबई स्थित कागजी कंपनियों, जिन्हें सूट केस कंपनियों के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से निवेश से संबंधित जांच का विवरण भी बताया। चूंकि जांच आधे रास्ते पर है, इसलिए हम स्थिति रिपोर्ट में उल्लिखित सभी विवरणों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

(12) आगे बताया गया है कि जांच के दौरान, आईएएस अधिकारियों और संबंधित मंत्रियों सहित कुल 140 गवाहों से पूछताछ की गई और 352 दस्तावेज एकत्र किए गए। सीबीआई के मुताबिक इनमें से कुछ और अहम गवाहों से पूछताछ की जानी है.

(13) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि दिनांक 05.10.2012 के आदेश के बाद, केवल अपीलकर्ता की हिरासत जारी रखने के लिए सीबीआई द्वारा इसे आगे बढ़ाना उचित नहीं है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि सीबीआई के अनुसार भी कई मंत्री और आईएएस अधिकारी शामिल हैं, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जहां तक उन आरोपों का सवाल है, तो सीबीआई का दावा है कि ए-1 और उसके सहयोगियों से जुड़े लेनदेन के विशाल आकार, विभिन्न लाभार्थियों, कंपनियों/व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, सीबीआई इसे जल्द पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। . यद्यपि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 167 के गैर-अनुपालन के मद्देनजर , अलग-अलग संस्थाओं, विभिन्न लेनदेन आदि के संबंध में रखी गई भारी सामग्री के मद्देनजर अपीलकर्ता वैधानिक जमानत

का हकदार है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2012 के आदेश में दी गई अनुमति के बावजूद, हम अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

(14) स्थिति रिपोर्ट और दिनांक 06.05.2013 को पुलिस उप महानिरीक्षक और मुख्य जांच अधिकारी, हैदराबाद द्वारा दिए गए जवाबी हलफनामे के रूप में सीबीआई द्वारा ्रस्तुत किए गए सभी विवरणों पर गौर करने पर, योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम उनका मानना है कि इस स्तर पर, अपीलकर्ता (ए-1) की रिहाई से जांच में बाधा आएगी क्योंकि यह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और भौतिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। यद्यपि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि चूंकि अपीलकर्ता किसी भी तरह से सत्ता में बैठे व्यक्तियों से जुड़ा नहीं है, इसलिए हमारा विचार है कि अपीलकर्ता के इस दावे पर विचार करते हुए सीबीआई द्वारा उठाई गई आशंका को हल्के में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बड़े मौद्रिक लेनदेन में अंतिम लाभार्थी और मुख्य साजिशकर्ता।

(15) आर्थिक अपराध एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ विचार करने की आवश्यकता है। गहरी साजिशों वाले और सार्वजनिक धन के भारी नुकसान वाले आर्थिक अपराध को गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसे गंभीर अपराध माना जाना चाहिए जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर

रहा है और इससे देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।

(16) जमानत देते समय, अदालत को आरोपों की प्रकृति, उसके समर्थन में सबूतों की प्रकृति, सजा की गंभीरता, आरोपी का चरित्र, परिस्थितियां जो आरोपी के लिए विशिष्ट हैं, को ध्यान में रखना होगा। मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित और अन्य समान विचार।

(17) इन सभी तथ्यों और मामले की विशालता को ध्यान में रखते हुए और योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आरोप पत्र दाखिल करने में जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने वाले सीबीआई के अनुरोध पर, हम हैं उनकी राय है कि इस स्तर पर अपीलकर्ता की रिहाई से जांच में बाधा आ सकती है। हालाँकि, हम सीबीआई को आज से 4 महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हैं। इसके बाद, जैसा कि पहले के आदेश दिनांक 05.10.2012 में देखा गया था, अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत करने के लिए स्वतंत्र है और यदि ऐसी कोई याचिका दायर की जाती है, तो ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान अपील के ख़ारिज होने से प्रभावित हुए बिना योग्यता।

(18) उपरोक्त टिप्पणी के साथ, अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुन्दरलाल बंशीवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।